

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 741
दिनांक 26 जुलाई, 2024 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय पोषण अभियान

741. श्री वरुण चौधरी:

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :-

- (क) उक्त योजना के प्रारंभ से गर्भवती महिलाओं और बच्चों में रक्ताल्पता को कम करने के लिए राष्ट्रीय पोषण अभियान के अंतर्गत निर्धारित और प्राप्त किए गए वार्षिक लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक गर्भवती महिलाओं और बच्चों में रक्ताल्पता को कम करने के लिए वर्ष-वार कितना व्यय किया गया है; और
- (ग) क्या बेहतर परिणामों के लिए योजना की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

**महिला एवं बाल विकास मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)**

(क) से (ग): भारत सरकार छह पहलों: प्रोफिलेटिक आयरन फोलिक एसिड अनुपूरण; आवधिक डीवार्मिंग; वर्ष भर व्यवहार परिवर्तन संचार अभियान; डिजिटल इनवेसिव हीमोग्लोबिनोमीटर और देखभाल उपचार बिंदु का उपयोग करके एनीमिया का परीक्षण; सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में आयरन फोलिक एसिड, फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों का प्रावधान; मजबूत संस्थागत तंत्र के माध्यम से स्थानिक क्षेत्र में एनीमिया के गैर-पोषण संबंधी कारणों को दूर करना इत्यादि के कार्यान्वयन के माध्यम से जीवन चक्र दृष्टिकोण में बच्चों (6-59 महीने), बच्चों (5-9 वर्ष), किशोरों (10-19 वर्ष), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं और प्रजनन आयु वर्ग (15-49 वर्ष) की महिलाओं में एनीमिया को कम करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एनीमिया मुक्त भारत (एमबी) कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा

है। एचएमआईएस 2023-24 के अनुसार देश भर में आयरन और फोलिक एसिड अनुपूरण कवरेज गर्भवती महिलाओं में 95.0% और 6-59 महीने के बच्चों में 38.4% है।

इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है और जो बेहतर पोषण सामग्री तथा प्रदायगी के माध्यम से कुपोषण की चुनौती का समाधान काना चाहता है। 15वें वित्त आयोग के तहत, आंगनवाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना (आकांक्षी जिलों और उत्तर-पूर्व क्षेत्र में 14-18 वर्ष) का मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के तहत विलय कर दिया गया था। मिशन पोषण 2.0 में कुपोषण में कमी और सामुदायिक भागीदारी, पहुँच, व्यवहार परिवर्तन और प्रचार के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य, कल्याण और प्रतिरक्षा के लिए एक कार्यनीतिक बदलाव किया गया है। मिशन पोषण 2.0 में ठिगनापन और एनीमिया के अलावा दुबलापन और अल्प वजन की व्याप्तता को कम करने के लिए आयुष प्रथाओं के माध्यम से मातृ पोषण, नवजात शिशु और छोटे बच्चे के आहार मानदंडों, गंभीर तीव्र कुपोषित (एसएएम)/मध्यम तीव्र कुपोषित (एमएम) के उपचार और कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) के माध्यम से पोषण संबंधी सहायता मिशन पोषण 2.0 के अभिन्न घटकों में से एक है जिसके तहत बच्चों (06 महीने से 6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्ल्यूएलएम) और किशोरियों (आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर राज्यों में 14 से 18 वर्ष) को पूरक पोषण प्रदान किया जाता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची-II में निहित पोषण मानकों के अनुसार पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। कुपोषण की चुनौती से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिए इन पोषण मानकों को संशोधित किया गया है। पुराने पोषण मानदंड अधिकांशतः कैलोरी-विशिष्ट थे। तथापि, संशोधित पोषण मानदंड विविध आहार के सिद्धांतों पर आधारित पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के मामले में अधिक व्यापक और संतुलित हैं जिसमें गुणवत्तायुक्त प्रोटीन, स्वस्थ वसा और सूक्ष्म पोषक तत्व के प्रावधान किये गए।

सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को केवल फोर्टीफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। सप्ताह में कम से कम एक बार पके हुए गर्म भोजन और टेक होम राशन (टीएचआर - कच्चा राशन नहीं) के लिए बाजारा के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

मिशन पोषण 2.0 के तहत की गई प्रमुख गतिविधियों में से एक सामुदायिक भागीदारी और जागरूकता प्रचार है जो पोषण संबंधी पहलुओं पर लोगों को शिक्षित करने के लिए जन-आंदोलन बनने की ओर अग्रसर है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः सितंबर और मार्च-अप्रैल के महीनों में मनाए जाने वाले

पोषण माह और पोषण पखवाड़ा के दौरान सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों के तहत नियमित रूप से संवेदीकरण गतिविधियों का संचालन और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एनीमिया के आसपास के मुद्दों को उच्च महत्व देने के लिए, पोषण अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा समर्पित "एनीमिया से संबंधित विषयों पर काम किया गया है। समुदाय आधारित कार्यक्रमों (सीबीई) ने पोषण प्रथाओं को बदलने में एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में कार्य किया है और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को हर महीने दो समुदाय आधारित कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता होती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम और मिशन पोषण 2.0 के तहत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित निधि नीचे सारणीबद्ध है:

वित्तीय वर्ष	राशि करोड़ में	
	एनीमिया मुक्त भारत	मिशन पोषण 2.0
2021-22	2203.71	18368.00
2022-23	823.00	19849.81
2023-24	862.80	21741.19
